भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1430

06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात आयात पर कार्बन टैरिफ लगाना

1430. श्री जग्गेश :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे यूरोपीय संघ द्वारा इस्पात के आयात पर कार्बन टैरिफ लगाने और इस क्षेत्र को कार्बनमुक्त करने की बढ़ती आवश्यकता के मद्देनजर राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) की समीक्षा शुरू कर दी है ;

(ख) क्या माल के उत्पादन और उपयोग पर इस नीति के पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने और इस बात की जांच करने का विचार है कि नई उभरती चुनौतियों के मद्देनजर क्या किन्हीं परिवर्तनों की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार ने समीक्षा के भाग के रूप में उद्योग और अन्य पणधारकों के साथ परामर्श शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क) से (घ): सरकार ने अर्काबनीकरण और यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) की शुरूआत सहित उभरती चुनौतियों के मद्देनजर विभिन्न सतत कदम उठाए हैं जो राष्ट्रीय इस्पात नीति की औपचारिक समीक्षा पर निर्भर नहीं हैं।

हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद सरकार ने इस्पात क्षेत्र के ग्रीन ट्रांजिशन के लिए रूपरेखा और कार्य-योजना तैयार की है। ऊर्जा दक्षता और प्रक्रिया दक्षता के लिए अन्य नीतिगत पहलों में इस्पात क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इस्पात विनिर्माण के लिए घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जिससे इस्पात विनिर्माण की प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति 2019 की अधिसूचना, और मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम 2021, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन के अंतर्गत प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना, जो ऊर्जा खपत को कम करने के लिए इस्पात उद्योग को प्रोत्साहन हेतु क्रियान्वयन आदि शामिल है।

******